

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

समक्ष – एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1878-दो/2005 , - विरुद्ध - आदेश दि.19-9-05  
- पारित द्वारा - कलेक्टर जिला भिण्ड - प्र०क० 38/1997-98 निगरानी

- 1- रामनारायण सिंह पुत्र गुन्दी सिंह
- 2- विजयसिंह पुत्र चरण सिंह
- 3- रामसेवक पुत्र ग्यादीन
- 4- रामकुमार पुत्र ग्यादीन
- 5- आशाराम पुत्र ठकुरी सिंह

सभी ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड  
विरुद्ध

—आवेदकगण

- 1- तेज सिंह पुत्र महाराज सिंह
- 2- महेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
- 3- श्रीमती दुलारी पत्नि स्व.शेरसिंह
- 4- बदन सिंह पुत्र शेरसिंह
- 5- नरोत्तम सिंह पुत्र शेरसिंह

सभी निवासी ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड  
6- म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड

—अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री पी०के०तिवारी)

(अनावेदक 1 से 5 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6-५ -2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/1997-98  
निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-9-2005 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,  
1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

K/ra



2/ प्रकरण का सारौंश यह है अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने प्रकरण कमांक 2/1981-82 X 57 में पारित आदेश दिनांक 1-10-1981 से ग्राम पुर की भूमि सर्वे कमांक 434 रकबा 0.14 है. (जिसका बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 436 बना है) अनावेदक कमांक 2 के हित में भूमिस्वामी घोषित कर प्रदान की गई। इस आदेश के विरुद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 38/1997-98 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19-9-2005 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि भूमि में से निकलने का रास्ता आवेदकगण को प्राप्त हो चुका है एवं वर्तमान में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं रहा है। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक को सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदकगण को बार-बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु सूचना पत्रों के निर्वहन की पुख्ता जानकारी न पाये जाने पर पंजीकृत डाक से सूचना भेजने के वाद भी वह अनुपस्थित है जिसके कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि ग्राम पुर की भूमि सर्वे कमांक 434 रकबा 0.14 है. का उपयोग पुरुखों के जमाने से समस्त ग्रामवासी घूरा डालने एवं कण्डे थापने तथा भूसे के कूप लगाने के लिये करते आ रहे हैं । यह भूमि ग्राम की आबादी के अन्दर है परन्तु अनावेदक कमांक 2 के पिता ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड को गलत जानकारी देकर तथा ग्रामवासियों को सूचना दिये बिना तथा ग्राम पंचायत से सार्वजनिक प्रयोग की जानकारी लिये बिना ही आदेश दिनांक 1-10-81 से भूमि 57 (2) के अंतर्गत अपने नाम करा ली, जबकि भूमि पर आज तक सभी ग्रामीण घूरा डालने एवं कण्डे थापने तथा भूसे के कूप लगाने के उपयोग में ले रहे हैं । अनावेदकगण अब जबरन भूमि पर कब्जे के प्रयास में है परन्तु कलेक्टर भिण्ड ने वास्तविकता जाने बिना केवल एक पक्षकार की सहमति मानकर निगरानी खारिज करने में भूल की है जबकि कोई भी पक्षकार राजीनामे के लिये अथवा दस्तखत करने के लिये तैयार नहीं है। फर्जी आदमी खड़ा करके कलेक्टर को गुमराह करके निगरानी खारिज कराना बताया गया। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

B  
1/19

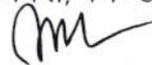
*(Signature)*

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम पुर की भूमि सर्वे क्रमांक 434 रकबा 0.14 है, जिसका बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 436 बना है, अनावेदक क्रमांक 2 के हित में अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 2/1981-82 X 57 में पारित आदेश दिनांक 1-10-1981 से भूमिस्वामी घोषित कर प्रदान की है। इसी भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न होने से शिकायती आवेदन कलेक्टर भिण्ड को दिनांक 2-2-1993 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे जाँच हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड को भेजा गया था। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 20-1-1993 के पद -6 में मौके पर जाँच करके स्थिति इस प्रकार बताई गई है :

“ रामसेवक s/o ग्यादीन सिंह का गोड़ा उक्त सभी व्यक्ति सर्वे नंबर 434 पर अतिक्रमण गौड़ा बनाकर व घूरा डालकर व कूप बनाकर व कन्डा आदि बना कर किये हुये हैं। इसी सर्वे नंबर में नीम के पेड़ 3, बबूल 2, बेरिया 5, मौके पर खड़ी है। मंदिर पर जाने की रास्ता पूर्व से है। कुआ भी उत्तर की ओर थी लेकिन (मंदा) “शब्द अपठनीय” बन जाने से अब रास्ता कम रह गई है और कुआ पास में होने से कीचड़ होती है जिसके कारण रास्ता में अवरोध आता है”

राजस्व निरीक्षक का उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन आने एवं स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/1997-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-9-2005 से यह निर्णय लेना कि तेज सिंह एवं महेन्द्र सिंह में राजीनामा होना प्रमाणित है एवं निगरानी निरस्त कर देना सार्वजनिक हित में न्याय करने की श्रेणी में नहीं है क्योंकि मूल मामला शासकीय भूमि के ग्रामीणों के सुखाचार से जुड़ा है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-9-2005 तथा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/1981-82 X 57 में पारित आदेश दिनांक 1-10-1981 त्रुटिपूर्ण होना पाये गये हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/1997-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-9-2005 तथा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/1981-82X57





में पारित आदेश दिनांक 1-10-1981 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड की ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह वाद विचारित भूमि का स्वयं स्थल निरीक्षण करें तथा सार्वजनिक हित में ग्राम पंचायत की राय लेकर एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।



(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

B  
2/1/81